प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले पैनल ने विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए अनेक कदमों की घोषणा की

इस्पात, वस्त्र, विमान और सार्वजनिक परिवहन में वैकल्पिक ईंधन के लिए समयबद्ध लक्ष्य तय किए गए

आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने, विनिर्माण के क्षेत्र में तेजी लाने तथा विनिर्माण के जरिए अधिक लोगों को रोजगार मुहैया कराने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति ने 2025 तक वार्षिक इस्पात उत्पादन क्षमता को 300 मिलियन टन करने तथा कपड़े के निर्यात में इस वर्ष तक 30 प्रतिशत की वृद्धि का लक्ष्य तय किया है। इसके अलावा भारत में असैन्य विमानों के विनिर्माण का काम शुरू करने और वैकल्पिक ईंधनों के माध्यम से सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को विकसित करने का निर्णय भी लिया गया है।

महत्वपूर्ण आर्थिक पैमानों में गिरावट तथा डॉलर के मुकाबले रूपए के अवमूल्यन की स्थितियों के बीच प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने विनिर्माण पर उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने इस बात पर खेद व्यक्त किया कि इलेक्ट्रॉनिक्स और दूरससंचार के क्षेत्र में देश में केवल नाममात्र की विनिर्माण क्षमता है। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि "आने वाले दशक में हमारी वृद्धि की रणनीति में विनिर्माण क्षेत्र काफी अहम होना चाहिए।" श्री सिंह ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना में काफी बड़ा बदलाव हुआ है।

उन्होंने कहा कि "कृषि जो कि अब भी हमारी जनसंख्या के 50 प्रतिशत से भी अधिक हिस्से की आजीविका है वह हमारे सकल घरेलू उत्पाद में केवल 15 प्रतिशत का ही योगदान करती है। यदि हमें 8-9 प्रतिशत की गति से वृद्धि करनी है तो विनिर्माण, खासतौर पर श्रम-आधारित विनिर्माण में सतत वृद्धि से ही इसे प्राप्त किया जा सकता है।" श्री सिंह, ने आगे कहा कि "जो लोग आजीविका के बेहतर अवसर चाहते हैं वे विनिर्माण के माध्यम से ही इसे प्राप्त कर सकते हैं।"

उन्होंने कहा कि "अक्सर हमारा उत्पादन मूल्य श्रृंखला के निचले सिरे पर होता है। हमारे निर्यात में कच्चा माल और प्राथमिक वस्तुएं शामिल हैं और आयात में बड़ी मात्रा में विनिर्मित वस्तुएं शामिल होती हैं।" मई में 20 बिलियन डॉलर तक के व्यापार घाटे के मद्देनजर उन्होंने कहा कि "अगर हमें आठ-नौ प्रतिशत (वार्षिक) की दर से वृद्धि करनी है तो खास तौर पर श्रम आधारित विनिर्माण में सतत वृद्धि के जरिए इसे प्राप्त किया जा सकता है। केवल विनिर्माण के जरिए ही आजीविका के क्षेत्र में बेहतर संभावनाएं उपलब्ध हो सकती हैं।"

लक्ष्य निर्धारण

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली विनिर्माण संबंधी उच्च स्तरीय समिति द्वारा तय समय सीमा

- 120 मिलियन टन की मौजूदा इस्पात उत्पादन की क्षमता को बढ़ाकर 2025 तक 300 मिलियन टन करने के लिए इस्पात मंत्रालय द्वारा रूपरेखा तैयार की जाएगी।
- वस्त्र निर्यात को इस वर्ष 30 प्रतिशत तक बढ़ाने के लिए वस्त्र सचिव की अध्यक्षता में आयोजित एक अंतर-मंत्रालयी समूह द्वारा चार सप्ताह के भीतर कार्य योजना तैयार की जाएगी।
- एक उच्च स्तरीय संचालन समूह द्वारा भारत में असैन्य विमानों के विनिर्माण संबंधी रूपरेखा तय की जाएगी।
- वैकल्पिक सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था के लिए पहली पायलट परियोजना को लागू करने के संबंध में अंतर-मंत्रालयी समूह द्वारा चार सप्ताह के भीतर कार्य योजना तैयार की जाएगी।

इस्पात

बैठक में 300 मिलियन टन इस्पात के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया। प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार "कम अवधि में जो परियोजनाएं विचाराधीन हैं उन्हें इस्पात मंत्रालय तथा कैबिनेट सचिवालय में नवीन निवेश सुविधा प्रणाली के जरिए वरीयता दी जाएगी।"

क्षमता विकास के लिए सरकार के स्वामित्व वाली स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया मौजूदा अवसंरचना प्रदान करेगी। यह सितंबर के अंत तक क्षमता विस्तार और विशेष प्रकार के इस्पात के उत्पादन के लिए योजना तैयार करेगी। इस क्षेत्र के लिए पूर्ण रूप से 300 मिलियन टन वार्षिक के इस्पात उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा। प्रधानमंत्री कार्यालय ने यह भी कहा कि क्योंकि निजी क्षेत्र को जमीन और इससे जुडी मंजूरी प्राप्त करने में परेशानी पेश आती है इसलिए राज्य सरकारें इसमें सक्रिय भूमिका अदा करेंगी।

इस वर्ष के लिए लक्ष्य क्षमता 2011-12 के 89 मिलियन टन के मुकाबले दुगुनी से कुछ अधिक यानि 120 मिलियन टन है। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि चुनिंदा स्थलों के लिए परियोजना विशिष्ट स्पेशल पर्पज व्हीकल (एसपीवी) (सहायक कंपनी के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला संदर्भ जिसकी परिसंपत्ति/ दायित्व संरचना और वैधानिक स्थिति इसके अपने दायित्वों को सुरक्षित बनाती है।) द्वारा जमीन को एकत्रित किया जाएगा और सभी जरूरी मंजूरियां ली जाएंगी ये एसपीवी जल और कच्चे माल का भी इंतजाम करेंगी। इसके बाद पारदर्शी तरीके से नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से निवेशकों को इसे प्रस्तुत किया जाएगा। आठ सप्ताह के समय के भीतर इस्पात मंत्रालय इस दिशा में एक योजना तैयार करेगी।

वस्त्र

ढ़ाका में राना प्लाजा इमारत के ढ़हने के बाद भारतीय वस्त्र क्षेत्र के पास विदेश में अपने आधार को मजबूत करने का नया अवसर है। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि इस वर्ष वस्त्र निर्यात को 30 प्रतिशत तक बढ़ाने के लिए तेजी से फैसले लिए जाएंगे। 2012-13 में यह 26 बिलियन डॉलर था इसमें 30 प्रतिशत की वृद्धि का तात्पर्य निर्यात को 34 बिलियन डॉलर तक पहुंचाना है।

प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार "इसके तहत कपास और अन्य फाइबर में मजबूती का इस्तेमाल रोजगार सृजन के लिए किया जाएगा और वैश्विक बाजार में हिस्सेदारी बढ़ाने का लक्ष्य प्राप्त किया जाएगा।"

इस रणनीति के मूल में व्यापक कदमों के माध्यम से देश के वस्त्र उद्योग में कपड़ों के क्षेत्र में प्रतिस्पर्द्धात्मकता को तेजी से बढ़ाना है। इस रणनीति के तत्वों में कार्य स्थल की उपलब्धता , श्रमिकों के लिए आवास की पर्याप्तता और सहूलियत, काम के समय में लचीलापन, वस्त्र संकुलों का लाभ और सर्वोत्तम तकनीक प्राप्त करना शामिल है।

विमान

इस बैठक में 70-100 सीटों वाले असैन्य विमानों को भारत में विकसित करने संबंधी निर्णय भी लिया गया। प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार "एक एसपीवी के जरिए विकास और उत्पाद को आरंभ करने का विचार है। एनएएल (नेशनल एयरोनॉटिक्स लिमिटेड), एचएएल (हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड) और देश के अन्य संस्थानों की डिजायन क्षमताओं का इस्तेमाल किया जाएगा।" राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धा परिषद के अध्यक्ष डॉ. वी. कृष्णमूर्ति की अध्यक्षता में एक संचालन समूह इस बारे में आगे काम करेगा।

गैर-पेट्रो सार्वजनिक परिवहन

बैठक में यह निर्णय भी लिया गया कि वैकल्पिक ईंधन पर आधारित सार्वजनिक परिवहन की प्रायोगिक परियोजना की शुरूआत की जाएगी। इसमें इलेक्ट्रिक और सम्मिश्रित वाहन- तिपहिया, मिनी बस, बस आदि शामिल होंगे। इसकी शुरूआत दिल्ली से की जाएगी बाद में अन्य मेट्रो शहरों में भी इसे शुरू किया जाएगा। दिल्ली में अगस्त महीने में इस पहल की शुरूआत की संभावना है। पहली परियोजना के लिए दिल्ली के मुख्य सचिव सहित एक अंतर-मंत्रालयी समूह अगले चार सप्ताह में इसके क्रियान्वयन की रूपरेखा तय करेगा।